कोविड 19 के संकट से निपटने के लिए आपातकालीन कदमों के लिए अपील

आदरणीय महोदय/महोदया

कोविड 19 एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है, जिसका करोड़ों लोगों की ज़िंदगी व आजीविका पर चिंताजनक असर पड़ने वाला है. हम आपसे आग्रह करते हैं कि देश की कम से कम 80 प्रतिशत आबादी को तुरंत आपातकालीन राहत मिले व अगले कुछ महीनों में मनरेगा का व्यापक विस्तार हो. इससे सम्बंधित हमारे निम्न सुझाव हैं:

आपातकालीन राहत

उसमें क्या शामिल हो

- जन वितरण प्रणाली के तहत आने वाले तीन महीनों (अप्रैल-जून) के लिए एक साथ मुफ़्त अनाज, खाद्य तेल, दाल, नमक, मसाला, व साबुन दिया जाए.
- राज्य-वार सामुदायिक रसोई योजनाओं या मध्याह्न भोजन की रसोइयों द्वारा कम से कम मई के अंत तक दिन में दो बार पका भोजन सबके लिए उपलब्ध हो.
- 1 अप्रैल तक सब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पेंशनधारियों को आने वाले तीन महीनों (अप्रैल-जून) की पेंशन राशि दी जाए.
- मनरेगा में मज़दूरी व सामग्री के रुपए 8,396 करोड़ की बकाया राशि का तुरंत भुगतान हो.
- बंदी के समय सब मनरेगा मज़दूरों को उनकी पूरी मज़दूरी मिले. यह भुगतान बेरोज़गारी भत्ता नहीं पर मज़दूरी दर पर हो, जबतक मज़दूर कोविड 19 के कारण कार्यस्थल पर नहीं आ सके.
- पीएम किसान योजना की पहली किश्त का तुरंत हस्तांतरण हो.
- प्रधान मंत्री आवास व स्वच्छ भारत मिशन योजनाओं की सब बकाया किश्तों का भुगतान हो.
- इन कदमों के अतिरिक्त, हर परिवार को अप्रैल व मई में आपातकालीन राहत के लिए रुपये 7,000 प्रति माह का भुगतान हो. इसके लिए कुल खर्च रुपये 3.75 करोड़ होगा (देश की कुल आमदनी का 1.92 प्रतिशत).

उसका वितरण तंत्र

- ऊपर वर्णित आपातकालीन राहत को लोगों के घर जाकर दिया जाए या राशन दुकानों पर.
- मनरेगा मज़दूरी, पेंशन व रुपये 7,000 प्रति माह का भुगतान नकद के रूप में हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों में अधिकाँश समय बहुत भीड़ होती है.
- राहत सामग्री/नकद लेने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो, क्योंकि उससे कोविड 19 के फैलने का ख़तरा है.
- जिन राज्यों में स्वयं सहायता समूहों का सुदृढ़ ढांचा है, वहां राहत सामग्री/नकद वितरण के लिए उनका सहयोग लिया जा सकता है. वितरण का अभिलेख रजिस्टरों में संधारित हो और उसे अलग अलग माध्यमों से सार्वजनिक किया जाए.

मनरेगा का विस्तार

- चूंकि शहरों में बंदी के कारण कई मज़दूर अपने गाँव वापस चले गए हैं, आने वाले महीनों में मनरेगा मज़दूरी की मांग बहुत बढ़ जाएगी. अन्य रोज़गार के विकल्पों के आभाव में ग्रामीण परिवारों के लिए मनरेगा की ज़रूरत और भी बढ़ जाएगी. इसलिए, मनरेगा में काम की गारंटी केवल 100 दिनों के लिए सीमित न हो.
- हर वार्ड में मनरेगा कार्यस्थल खुले और काम करने के इच्छुक हर व्यक्ति को काम मिले, अगर उनका नाम ई-मास्टर रोल पर नहीं हो तब भी.
- मनरेगा में संभावित कार्यों का दायरा भी बढ़ाया जाए, ताकि बागवानी के कार्य, जंगल सम्बंधित कार्य व घर से किए जा सकने वाले कार्य भी शामिल हो सके. कोविड 19 से बचने के लिए प्रयोग होने वाली सामग्री का उत्पादन भी मनरेगा के तहत हो सकता है.
- मनरेगा का शहरी क्षेत्रों में भी विस्तार हो, चूंकि कई मज़दूर वापस गाँव नहीं जा पा रहे और कोविड 19 से हुई आर्थिक मंदी से निपटने के लिए शहरों में भी रोज़गार की गारंटी आवश्यक है.

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: Amit Basole (9619649948), Anindita Adhikari (9871832323), Rajendran Narayanan (962031842), Rakshita Swamy (9818838588)

Endorsements (in alphabetical order)

1. Aaditeshwar Seth, Co-founder Gram Vaani and Associate Professor, IIT Delhi
2. Abey George, Associate Professor, Kerala Institute of Local Administration
3. Abhay Kumar, Former Member, Central Employment Guarantee Council
4. Amit Basole, Associate Professor of Economics, Azim Premji University
5. Amrita Johri, Satark Nagrik Sangathan, New Delhi
6. Anindita Adhikari, Doctoral Student, Brown University
7. Anjali Bhardwaj, Satark Nagrik Sangathan, New Delhi
8. Ankita Aggarwal, Doctoral Student, City University of New York
9. Annie Raja, General Secretary, National Federation of Indian Women
10. Anuradha De, Director, CORD, New Delhi
11. Anuradha Talwar, West Bengal Farm Workers Union
12. Apurva Bamezai, Doctoral Student, University of Pennsylvania
13. Arindam Banerjee, Associate Professor, Ambedkar University Delhi
14. Arjun Jayadev, Professor of Economics, Azim Premji University
15. Aruna Roy, President, National Federation of Indian Women
16. Ashish Ranjan Jha, Social Activist
17. Ashwini Deshpande, Professor of Economics, Ashoka University
18. Ashwini Kulkarni, Pragati Abhiyan, Nashik
19. Awanish Kumar, Assistant Professor, St Xavier's College (Autonomous), Mumbai
20. Babu Mathew, Resident Professor and Director, Centre for Labour Studies, NLSIU, Bengaluru
21. Bina Agarwal, Professor, University of Manchester, United Kingdom.
22. C. Rammanohar Reddy, Editor, *The India Forum*
23. Chakradhar Buddha, LibTech India
24. Debmalya Nandy, Social Activist

25. Deepak Malghan, Associate Professor of Economics, Indian Institute of Management, Bangalore
26. Dipa Sinha, Assistant Professor of Economics, Ambedkar University Delhi
27. Harsh Mander, social activist
28. Hema Swaminathan, Associate Professor of Economics, Indian Institute of Management, Bangalore
29. Himanshu, Jawaharlal Nehru University
30. Jagdeesh Rao, Chief Executive, Foundation for Ecological Security
31. James Herenj, Convenor, Jharkhand NREGA Watch
32. Jayati Ghosh, Professor of Economics, Jawaharlal Nehru University
33. Jean Dreze, Visiting Professor, Department of Economics, Ranchi University
34. Jeevika Shiv, Social Activist
35. Jyothi Krishnan, Social Accountability Resource Unit
36. Karuna M, Rural Development Consultant
37. Kavita Krishnan, AIPWA, and All India Agricultural and Rural Labourers Association
38. Kavita Shrivastava, PUCL
39. M. R. Sharan, Doctoral Student, Harvard University
40. Maitreesh Ghatak, Professor, Department of Economics, London School of Economics
41. Nikhil Dey, Founder Member, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan
42. Poonam Muttreja, Executive Director, Population Foundation of India, New Delhi, India.
43. Rahul Lahoti, Visiting Faculty, Azim Premji University
44. Rajendran Narayanan, Assistant Professor, Azim Premji University
45. Rajesh Veeraraghavan, Assistant Professor, Georgetown University
46. Rakshita Swamy, Lead Coordinator, Social Accountability Resource Unit
47. Rohit Azad, Assistant Professor, CESP, JNU
48. Sakina Dhorajiwala, LibTech India
49. Shantha Sinha, former chairperson NCPCR
50. Sona Mitra, Economist, New Delhi
51. Dr. Sylvia Karpagam, Public Health Doctor and Researcher, Bangalore
52. Vinay Sreenivasa, Advocate, Bangalore
53. Yogendra Yadav, Social Activist